40,000 डाई ड्यू टू एयर पलूशन एवरी यिअर शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1530. **श्री राम जेठमलानी:**
श्री ओम प्रकाश कोहली:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 अक्तूबर, 1996 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में '40,000 डाई ड्यू एयर पलूशन एवरी यिअर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देश में वायु प्रदूषण के कारण बहुत बड़ी संख्या में अकाल मौतें हो रही हैं,

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या आकलन है और प्रदूषण को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई है,

(घ) क्या यह भी सच है कि देश में जल तथा वायु प्रदूषण के कारण अस्वास्थ्यकर वातावरण पैदा होता है और इसके परिणामस्वरूप 24,500 करोड़ से भी अधिक रुपये अतिरिक्त वार्षिक व्यय के रूप में स्वास्थ्य संबंधी क्रियाकलापों पर खर्च किये जाते है, और

(ङ) यदि नहीं तो इस संबंध में सरकार का क्या आकलन है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद): (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक ने "दि कास्ट ऑफ इनैक्शन : वैल्यूइंग दि इकॉनामी वाइड कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंटल डीग्रेडेशन इन इंडिया" शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें, पर्यावरणीय अवक्रमण के कारण पूर्वानुमानित लागत और क्षति की समीक्षा की गई है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत के 36 शहरों में जन्मदर और मृत्युदर में कमी होने का अनुमान है यदि इन शहरों में प्रदूषकों का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक औसत मानक तक कम कर दिया जाए। कुल 40,000 से अधिक लोगों को अकाल मृत्यु से बचाया गया। इसमें दिल्ली के 7,500, कलकत्ता के 5700 और मुम्बई के 4,500 लोग शामिल हैं।

(ग) से (ङ) दस महानगरों में मानीटर किए गए परिवेशी वायु गुणवत्ता आंकड़ों से विदित है कि दिल्ली, कलकत्ता और मुम्बई में निलंबित कणिकीय पदार्थों का स्तर निर्धारित सीमा से ज्यादा है लेकिन सल्फर डायाक्साइड और नाइट्रोजन आक्साइड अपनी निर्धारित सीमा से नीचे हैं। तथापि जन्मदर और मृत्युदर के संबंध में कोई निर्णायात्मक सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि प्रदूषित जल और वायु पर्यावरण को अस्वास्थ्यकर बना देते हैं। विश्व बैंक की उपर्युक्त रिपोर्ट से पता चलता है कि वायु और जल प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलापों पर प्रति वर्ष 10,446 मिलियन डालर खर्च करने पड़ते हैं। सरकार ने पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- प्रदूषण निवारण के लिए एक व्यापक नीतिगत विवरण तैयार किया गया है जिसमें विकास योजना के पर्यावरणीय और आर्थिक पहलुओं के एकीकरण का प्रस्ताव है। इसमें प्रदूषण निवारण के निरोधात्मक पहलुओं और औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए प्रौद्योगिकीय निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
- उद्योगों के लिए स्थान और उनके संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश बनाए गए हैं।
- प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करने और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से उद्योगों के स्थानान्तरण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।
- उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण/मानीटरन उपकरणों के लिए सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट दी जाती है।
- लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों में साझे बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने की योजना कार्यान्वित की जा रही है। लगभग 60 बहिस्राव शोधन संयंत्रों को स्वीकृति दी गई है और वे निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं।
- लघु और मझौले उद्योगों में प्रदूषण निवारण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित परियोजनाएं प्रारंभ की है।
- लघु उद्योगों के समूहों में "वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल्स" (अपशिष्ट न्यूनीकरण केन्द्र) स्थापित करने की परियोजना।
- राष्ट्रीय परिषद में "नेशनल क्लीनर प्रोडक्शन सेंटर" (राष्ट्रीय स्वच्छ उत्पादन केन्द्र) की स्थापना की परियोजना।
- पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत उद्योगों के 39 श्रेणियों के लिए बहिस्राव मानक अधिसूचित किए गए हैं।

- अत्याधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 श्रेणियों के उद्योगों की कुल 1551 इकाइयों में से 1259 उद्योगों ने पहले ही प्रदूषण नियंत्रण की पर्याप्त सुविधाएं लगा ली हैं जो कि निर्धारित मानकों का अनुपालन करती है। 112 इकाइयों को बंद कर दिया गया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमित रूप से मानीटरन की जा रही है और दोषी इकाइयों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
- देश में प्रदूषण निवारण के लिए 24 समस्याग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाया जा चुका है। 14 क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं तैयार कर ली गई है जो कि कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है।
- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं। इनमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे आवासीय, औद्योगिक और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए मुख्य वायु प्रदूषकों के मानक भी शामिल है।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देशभर में फैले 290 परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरन केन्द्रों और 480 जल प्रदूषण मानीटरन केन्द्रों के नेटवर्क की सहायता से परिवेशी वायु तथा जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है।
- पैट्रोल एवं डीजल से चलने वाले सभी श्रेणी के वाहनों के लिए 1.4.96 से कठोर उत्सर्जन मानक शुरू किए गए हैं। इन्हें 1.4.2000 से और अधिक कठोर बनाया जाएगा। इससे स्वच्छ वाहन प्रयोग में आएंगे और उनमें बेहतर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से उत्सर्जन में कमी आएगी।
- केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को सलाह दी है कि वे सड़क पर चलने वाले वाहनों से उत्पन्न धुएं के लिए मानकों को लागु करें और आम जनता में वाहनों के रख-रखाव, वाहनों के प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों और उत्सर्जन मानकों के उल्लंघन के सुधारात्मक उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करें।
- दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता तथा चिन्नई चार महानगरों में जून 1994 से कम सीसायुक्त पैट्रोल शुरू कर दिया गया है। इसके पश्चात् उक्त चार महानगरों में 1.4.1995 को सीसा रहित पैट्रोल शुरू किया गया है।
- सरकार चरणबद्ध रूप से सीसा रहित पेट्रोल तथा कैटेलैटिक कनवर्टर लगे वाहन शुरू करने तथा डीजल से चलने वाले स्वच्छ वाहनों के लिए कम सल्फरयुक्त डीजल शुरू करने की एक बड़ी कार्य योजना कार्यान्वित कर रही है। पेट्रोल और डीजल के लिए ईंधन गुणात्मक मानक अधिसूचित कर लिए गए हैं।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा देश के 12 प्रमुख शहरों में वाहन प्रदूषण के संबंध में व्यापक सर्वेक्षण किए गए हैं।

Cultivation of Coloured Cotton

1531. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Govemment are aware of the projects proposed to be implemented for cultivation of coloured cotton on a large scale;

(b) if so, the likely impact of these projects on environment crop fields and possibility of condemnation leading to crisis situation;

(c) the reaction of the Government to the proposal of Cotton Corporation of India which has made much headway in promoting coloured cotton cultivation;

(d) the policy of the Govemment in regard to cultivation of coloured cotton;

(e) the steps taken to seek international cooperation to augment production of long staple high yielding varieties of cotton and results achieved so far; and

(f) the significant research achievement of Cotton Research Institute during recent years?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) to (d) At present, there is no project proposal for the cultivation of coloured cotton on a large scale. However, Indian Council of Agricultural Research and Cotton Corporation of India have initiated a network of research programme in certain parts of the country. The cultivation of naturally coloured cotton will not have any adverse affect on environment. However, its cultivation is to be confined to restricted areas in order to avoid contamination of white cotton.